Ok"ki % 42(vad % 02 (Qjojh % 2020(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स

कान्फ्रेन्स का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष हेमलता

कान्फ्रेन्स का समापन करते हुए महासचिव तपन सेन

सीटू केन्द्र की पत्रिकाओं के लिए खबरें, रिपोर्टें, फोटो आदि कृपया इस मेल पर भेजें– *citujournals@gmail.com*

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स

उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते महासचिव; मंच पर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता और डब्ल्यूएफटीयू के अध्यक्ष

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते डब्ल्यूएफटीयू अध्यक्ष

सम्पादकीय

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स तात्कालिक कार्य

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

फरवरी 2020

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के. हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे. एस. मजुमदार~~

सदस्य

~~तपन सेन,~~

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

Lo.k t ;rh o"k e 16oh dkUÝUl 5

lhVw dh 16oh dkUÝUl dk vkoku

& riu lu 6

8 tuojh 2020 &

etnjk dh vke gMrky 21

jkT;k l ,o m|kx 20

miHkDrk eY; lpdk 26

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स एक ओर मजदूर वर्ग और देश की जनता के समक्ष आज तेजी से बदलती स्थिति, और नई बड़ी चुनौतियों के बीच की खाई को; और दूसरी ओर इसके परम्परागत, यांत्रिक, ढर्रेबाजी के रुझानों और संख्याओं एवं संरचनाओं में संगठनात्मक कमियों को आगे लेकर आयी है।

शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ट्रेड यूनियनों, मजदूर–किसान संगठनों, के राष्ट्रीय एकजुट मंच और सभी तबकों एवं जन संगठनों के व्यापक जनवादी मंच उभर कर आगे आये हैं। इन राष्ट्रीय मंचों द्वारा भी समय–समय पर एकजुट कार्रवाहियों के आह्वान हुऐ हैं। इन आह्वानों पर सकारात्मक और बड़ी प्रतिक्रियाऐं आती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के प्रमुख हिस्से में हालांकि स्वतःस्फूर्तता चरित्र के रूप में है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए–एनआरसी–एनपीआर के खिलाफ स्वागत योग्य स्वतःस्फूर्त आंदोलन में भी दिखता है, जहाँ जनवादी आंदोलन कम है। मजदूर वर्ग नियति निर्धारक है। इन ज्यादातर स्वतःस्फूर्त आंदोलनों को लक्ष्यपरक दिशा देनी होगी। इसका कोई विकल्प नहीं है।

देशव्यापी स्तर पर, विशेष रुप से जहाँ जनवादी आंदोलन कमजोर है, सीटू ने मजदूर वर्ग के बीच सीमित पहुँच ही बनायी है। तुलनात्मक रूप से, जहाँ जनवादी आंदोलन बड़ा व व्यापक है जैसे कि केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में वहाँ संगठनात्मक पहुँच व्यापक एवं गहरी है। बाकी राज्यों में भी व्यापक विविधताएं हैं। इसलिए, संगठन का पुर्ननिर्माण करने और उसे पुनः उन्मुख करने के लिए राज्य–विशिष्ट कार्यक्रम होना चाहिए।

. . वीं कान्फ्रेन्स ने औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक फैलाव को विस्तारित करने; मौजूदा क्षेत्रों में इसे गहरा करने; और मजदूरों के साथ कार्यस्थल और आवासीय क्षेत्रों में जीवंत सम्पर्क बनाने के कार्य को तात्कालिक कार्य के तौर पर रेखांकित किया है।

कान्फ्रेन्स ने सभी स्तरों पर अपने कैडरों को वैचारिक और राजनीतिक रूप से फिर से उन्मुख करके उनमें गुणात्मक परिवर्तन पर जोर दिया है, ताकि उनमें से हजारों मजदूरों और जनता के बीच राजनीति और नीतियों पर अभियान चलाकर मजदूरों और जनता के आंदोलन को उद्देश्यपूर्ण दिशा में लक्षित किया जा सके।

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स

नये चुने गये पदाधिकारीगण

अध्यक्ष : के. हेमलता (म)

महासचिव : तपन सेन

कोषाध्यक्ष : एम.एल. मलकोटिया

उपाध्यक्ष

1- ,-d- iùukHku
2- t-,l- etenkj
3- ,- lkUnjjktu
4- d-vk- gchc
5- d-d- fnokdju
6- vFkykoÍe vukUnu
7- elhidÍh vEek ¼e½
8- ekfud M
9- ekyrh fpÍhckc ¼e½
10- j?kukFk flg
11- fc"u ekgUrh
12- ,l- ojky{eh ¼e½
13- Mh-,y- djkM
14- cch jkuh ¼e½
15 ,e- lkbickc
16- lHkk"k e[kth

सचिव

1- ,l- nojk;
2- bykeje djhe
3- d'ehj flg Bkdj
4- Á'kkUr ,u- pk/kjh
5- th- ldekju
6- ih- uUndekj
7- ,e-,- xQj
8- Mh-Mh- jkekuUnu
9- ,-vkj- flU/k ¼e½
10- d- pUnu fiYy
11- ehuk{kh lUnje
12- m"kk jkuh ¼e½
13- vukfn lkg
14- pDdk jkey
15- e/kferk cU/kkik?;k; ¼e½
16- vferko xgk
17- vkj- d#eyk;u
18- riu 'kek
19- Áekn Á/kku
20- fjDr

स्थायी आमंत्रित – बासुदेव आचार्य

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

स्वर्ण जंयती वर्ष में आयोजित 16वीं कान्फ्रेन्स

mn?kkVu lekjkg o x.kr= fnol

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) की 16वीं कान्फ्रेन्स संगठन के स्वर्ण जंयती वर्ष में 23–27 जनवरी, 2020 तक चेन्नई में आयोजित हुई। सीटू के दिवंगत राष्ट्रीय नेता तथा उसके पूर्व महा सचिव मोहम्मद अमीन के नाम पर बनाये गये नगर में 23 जनवरी को सम्मेलन की शुरूआत अध्यक्ष के हेमलता द्वारा सीटू का झडा फहराये जाने के साथ हुई।

भारत के संविधान के धर्म निरपेक्षता और जनवाद के आधार को बनाये रखने के लिए 23 जनवरी (नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मदिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) व 30 जनवरी (महात्मा गांधी बलिदान दिवस) को मनाने के राष्ट्रीय आहवान के अनुरूप सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स ने राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी हस्ती नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी को झंडारोहण के दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और सीटू के अध्यक्ष, महासचिव व अन्य नेताओं ने उन्हें व शहीदों को विशेष रुप से बनायी गई शहीद वेदी पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।

इंडियन नेशनल आर्मी (आइएनए) में नेताजी के तीन घनिष्ठ सहयोगी –पी.के. सहगल, जी.एस. ढिल्लों,.शाहनवाज़ खान (एक हिन्दू, एक सिख व एक मुसलमान) और जय हिन्द का जोरदार सेल्यूट राष्ट्रीय एकता व घर्म निरपेक्ष भारत का प्रतीक बन गये। शहीदों की याद में जलती मशालों के साथ समस्त जत्थे सारे तमिलनाडु से गुजरते उद्घाटन समारोह में सम्मेलन स्थल पर पहुँचे और मशालों को सीटू के राष्ट्रीय व राज्य के नेताओं को सौपा गया।

गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को सम्मेलन स्थल पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया; प्रतिनिधियों ने भारत के संविधान के बुनियादी मूल्यों व सिद्वातों की रक्षा करने तथा स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के साथ ही शोषण को समाप्त करने के सीटू के संविधान के उद्देश्य की शपथ ली। प्रतिनिधियों ने सम्मेलन स्थल के समाने सी ए ए, एन आर सी, एन पी आर के विरोध में तथा गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार के मेहमान के रुप में बोलसानारों की यात्रा का विरोध करते हुए मानव श्रंखला बनाई।

उद्घाटन सत्र

उद्घाटन सत्र की शुरुआत सीटू के राष्ट्रीय नेता व उसके पूर्व उपाध्यक्ष सुकोमल सेन के नाम पर बनाये गये मंच पर हुई। 26 राज्यों से आये व 4621 यूनियनों तथा 58,68,669 सदस्यों का प्रातीनिधित्व कर रहे 1,991 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया जिनका 23 प्रतिशत महिलायें थी; 10 बिरादाना प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित थे।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता हेमलता ने की। स्वागत समिति के अध्यक्ष ए. सौंदरराजन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सीटू के सम्मेलन में शामिल होने विशेष रुप से भारत आये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (डब्ल्यू एफ टी यू) के अध्यक्ष माइकल मकवाईबा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच में शामिल सभी 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं –एटक की महासचिव अमरजीत कौर, इंटक के उपाध्यक्ष मुरुगेषन; एचएमएस के अध्यक्ष राजा श्रीधर; एआइयूटीयूसी के अध्यक्ष रामकृष्णन; एक्टू के अध्यक्ष वी शंकर; सेवा की सोनिया; यूटीयूसी के महासचिव अशोक घोष; एलपीएक के महासचिव षणमुगम तथा टीयूसीसी के उपाध्यक्ष कदीरवन ने बधाई देते हुए सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होने देश की एकता को बचाने तथा मोदी नेतृत्व की भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी, जन विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों को परास्त करने के लिए संयुक्त संघर्षो को मजबूत करने पर जोर दिया। उद्घाटन सत्र में सम्मेलन ने सर्व सम्मति से अतंर्राष्ट्रीय एकजुटता पर तथा राष्ट्रीय एकता पर दो प्रस्तावों समेत तीन प्रस्तावों को पारित किया। अध्यक्ष हेमलता ने फ्रांस के हड़ताली रेल व सड़क परिवाहन मजदूरों के साथ अतंर्राष्ट्रीय एकजुटता जाहिर करते हुए प्रस्ताव पेश किया। सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव को महासचिव तपन सेन

ने पेश किया तथा धारा 370 को समाप्त किये जाने, राज्य को तोड़े जाने तथा जम्मू–कश्मीर में लोगों के अधिकारों को कुचले जाने के विरोध में प्रस्ताव को उपाध्यक्ष जे एस मजुमदार द्वारा पेश किया गया।

प्रतिनिधि सत्र

23 मई को दोपहर बाद प्रतिनिधि सत्र की शुरुआत कोषाध्यक्ष एम.एल. मलकोटिया द्वारा शोक प्रस्ताव पेश किये जाने और प्रतिनिधियों द्वारा मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि दिये जाने के साथ हुई।

सम्मेलन के अध्यक्ष मंडल में अध्यक्ष व उपध्यक्ष तथा सचिवमंडल ने संचालन समिति के रुप में कार्य किया। सम्मेलन ने प्रस्ताव समिति, परिचय पत्र समिति और ब्यौरा समिति का चुनाव किया। सीटू के सम्मेलन मे पहली बार 6 भाषाओं –बांग्ला, हिंदी, कन्नड, मलयालम, तमिल व तेलगु में साथ–साथ अनुवाद की व्यवस्था की गई थी।

बिरादराना जन संगठनों के नेता– एआइकेएस महासचिव हन्नान मोल्ला; एआइएडब्ल्यूयू महासचिव बी वेंकट; एडवा महासचिव मरियम ढवले; डीवाइएफआई महासचिव अवय मुखर्जी तथा एसएफआई के अध्यक्ष पी सानू ने सम्मेलन को शुभकामनायें देते हुए संबोधित किया।

बिरादराना प्रतिनिधियों–एआइआइईए से गिरिजा; बेफी से नंद कुमार; आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स कन्फेडरेशन के महासचिव एम कष्णन; बीएसएनएलईयू के महासचिव पी अभिमन्यु; एफएमआरएआई के महासचिव शान्तनु चटर्जी तथा अन्य ने भी सम्मेलन को बधाई देते हेतु संबोधित किया।

हेमलता के अध्यक्षीय भाषण के बाद तपन सेन ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की जिसके दो हिस्से थे। पहला देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में, मजदूरों के हालातों उनके संघर्षो व अनुभवों के बारे में था; और दूसरा भाग संगठन पर था। लेखे–जोखे का आडिटिड बयान एम.एल. मलकोटिया द्वारा पेश किया गया। भविष्य के कामों के बारे में प्रस्ताव महासचिव द्वारा पेश किया गया।

महासचिव की रिपोर्ट पर 95 प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया। सभी ने रिपोर्ट की स्थापनाओं व कार्यों का अनुमोदन व समर्थन किया। तपन सेन द्वारा बहस का जवाब दिये जाने व सार पेश किये जाने के बाद महासचिव की रिपोर्ट, कार्यों व स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रतिनिधि सत्र में कई और प्रस्ताव भी पारित किये गये– (1) त्रिपुरा की संधर्षशील जनता व मजदूर वर्ग की एकजुटता में; (2) केरल की एलडीएफ सरकार के साथ भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव व राज्य के मामलों में राज्यपाल के हस्तक्षेप के खिलाफ; (3) महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के खिलाफ तथा बराबरी के दर्जे की माँग करते हुए 6 मार्च, 2020 को देशव्यापी गिरफ्तारी कार्यक्रम के लिए; (4) योजना मजदूरों की माँगों पर; (5) नाजियों के स्वयंभू प्रशंसक तथा भाजपा की मोदी सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह मेहमान के रूप में आमंत्रित ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसानारो की यात्रा के खिलाफ; तथा (6) बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में पारित प्रस्ताव इनमें शामिल थे।

मलकोटिया द्वारा परिचयपत्र समिति की रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 39 सदस्यीय नये सचिवमंडल का चुनाव किया जिसमें हेमलता को पुनः अध्यक्ष, तपन सेन को महासचिव व एम.एल. मलकोटिया को कोषाध्यक्ष चुना गया। आठ नये पदाधिकारी चुने गये; 425 सदस्यीय जनरल कौंसिल चुनी गयी जिसने 125 सदस्यीय वर्किंग कमेटी का चुनाव किया।

आयोग

26 जनवरी को प्रतिनिधि चार अलग–अलग आयोगों में बैठे– (1) वैकल्पिक नीतियों के लिए संधर्ष (2) बेरोजगारी तथा कार्यस्थल पर श्रम के संघटन में बदलाव, (3) श्रम कानूनों का संहिताबद्ध किया जाना, (4) सामाजिक अत्याचार। कुल मिलाकर 219 प्रतिनिधियों ने इन आयोगों की चर्चाओं में योगदान किया और 50 से ज्यादा ने लिखित में अपने सुझाव दिये। चारों आयोगों की रिपोटों को प्लेनरी सत्र में पेश किया गया।

समापन सत्र

अध्यक्षमंडल की ओर से हेमलता ने सभी प्रतिनिधियों का सम्मेलन की कार्यवाहियों के सुचारू संचालन में योगदान के लिए तथा सम्मेलन के आयोजन के लिए शानदार इंतजामों के लिए स्वागत समिति को धन्यवाद दिया।

अपने समापन भाषण में उन्होंने काम के तौर–तरीकों को बदलाने की जरूरत तथा सांगठनिक व विचार धारात्मक रूप से सीटू को मजबूत किये जाने पर जोर दिया। उन्होंने यह कहते हुए सम्मेलन का समापन किया कि दुनिया की कोई भी ताकत एकजुट मजदूर वर्ग को नहीं हरा सकती है। और जिन्होंने भी पहले ऐसा करने की कोशिशे की वे सभी इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिये गये।

पश्चिम बंगाल राज्य समिति के अनुरोध पर यह तय किया गया कि सीटू के स्वर्ण जयंती समारोहों का समापन 30 मई, 2020 को कोलकाता में होगा जहाँ 50 वर्ष पूर्व स्थापना सम्मेलन हुआ था। इसके बाद ही नई चुनी गई जनरल कौंसिल की वहाँ पहली बैठक होगी।

ए. सौंदरराजन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए तालियों के बीच अग्रणी वालंटियर्स से प्रतिनिधियों का परिचय कराया।

ताजा महत्व के विभिन्न विषयों पर 18 सेमिनार, सम्मेलन के पहले राज्य के विभिन्न भागों में आयोजित किये गये थे। तमिलनाडु की लोक संस्कृति को दर्शाता एक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस अवसर पर समुद्र किनारे आयोजित किया गया।

रैली व आम सभा

16वीं कान्फ्रेन्स के मौके पर सीटू की तमिलनाडु राज्य समिति ने सैदापेट मेट्रों स्टेशन से एक विशाल रैली निकाली जो अन्ना सालई होते हुए वाईएमसीए नंदानम मैदान पहुँच कर आम सभा में बदल गई। यह रैली एक और वजह से भी महत्वपूर्ण है। यह पहला जुलूस था जिसे 20 वर्ष बाद इस व्यवस्त रास्ते से गुजरने की इजाजत मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी।

जोश व उत्साहपूर्ण ढंग से पेश किये जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद ए सौंदरराजन की अध्यक्षता में आम सभा की शुरूआत हुई। सभा को संबोधित करते हुए सीटू अध्यक्ष हेमलता ने मोदी सरकार के कारपोरेट हितैषी हमलों का जिक्र किया जो मजदूरों के संधर्षों के दम पर हासिल अधिकारों पर किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीटू की अभी संपन्न 16वीं कान्फ्रेन्स ने चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संकल्प लिया है; सीटू आर एस एस से संबद्ध बी एम एस को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों की एकता के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने 8 जनवरी की मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल का जिक्र किया जिसमें अन्य मेहनतकशों ने हिस्सेदारी की, उन्होंने सीएए को र६ किये जाने समेत 13 सूत्री मांग पत्र की चर्चा की जिस पर संध र्षों का निमार्ण किया जाना है और इसके आधार पर किसानों, खेतमजदूरों, छात्रों व बेरोजगार युवाओं के साथ व्यापकतम एकता बनायी जानी है।

महासचिव तपन सेन ने कहा कि मजदूर वर्ग सरकार के भेदभावपूर्ण फैसलों पर सवाल करने से पीछे हटने वाला नहीं है; वह धर्म के आधार पर मेहनतकश जनता को बांटने की भाजपा सरकार की कोशिशों व सांप्रदायिक अभियान का मुकाबला करेगा। उन्होंने, सीएए, एनआरसी व एनपीआर के बारे में मेहनतकश जनता के बीच व्यापक सधन प्रचार चलाने के सीटू के फैसले के बारे में बताया।

उपाध्यक्ष ए के पद्मनाभन ने सिंगारावेलार के महान योगदान को याद किया और मजदूरों से आहवान किया कि वे सम्मेलन के फैसले के अनुरूप 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या किये जाने वाले दिन 5.17 बजे शाम को देश भर में आवाजाही को रोकना सुनिश्चित करें।

डब्लूएफटीयू अध्यक्ष माइकल मकवाईबा ने अपने जोशीले भाषण में मजदूरों से कहा कि मजदूरों के साथ रंग, नस्ल व धर्म से परे जाकर पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण हो रहा है, मेहनतकशों को अपने अधिकारों के प्रति व राजनीतिक रूप से चेतनाबद्ध होना होगा।

मेहनतकश जनता ही पथ्वी के संसाधनों की असली मालिक है और यह ट्रेड यूनियनों का दायित्व है कि मजदूर वर्ग को यह समझायें। उन्होंने आश्वस्त किया कि डब्ल्यूएफटीयू भारत के मजदूर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा।

सौंदरराजन ने कहा कि आर्थिक मंदी और बड़ी संख्या में कर्ज में दबे किसानों की आत्महत्याओं के बावजूद भाजपा सरकार ने कारपोरेटों को 1.25 लाख करोड़ रूपये की राहत दी है और आरबीआई तक को लूट लिया है। मोदी के 6 वर्ष के शासन में बढ़ते ठेकाकरण के साथ मजदूरों की संख्या को कम किया जा रहा है। परिस्थिति की मांग है कि मजदूरों के जुझारू संधर्ष हो तथा सीटू के ''एकता और संघर्ष' के नारे पर ट्रेड यूनियन की एकता व ताकत को बढ़ाया जाये। *(योगदानः वी बी गणेशन)*

कार्यों के बारे में

प्रमुख उद्देश्य

– 'जिन तक न पहुँचे उन तक पहुँचना';
– 'मुद्दों को नीतियों से जोडें और इन नीतियों को बनाने वाली राजनीति का पर्दाफास करो';
– संयुक्त संघर्षों को नयी उँचाईयों तक लेकर जायें;
– सभी विभाजनकारी एवं विघटनकारी ताकतों से लड़ो।

तात्कालिक कार्यः

अभियानों और संघर्षों से संबंधितः

सीएए/एनपीआर/एनआरसी के खिलाफ – फरवरी–मार्च 2020 के दौरान

- मानव श्रंखला और 'इंजन ऑफ' कार्यक्रमों में 30 जनवरी को गांधीजी की शहादत के दिन भाग लें;
- डोर टू डोर और कार्यस्थलों पर व्यापक अभियान के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से जनता से संपर्क करके आपसी चर्चा के द्वारा एनपीआर के सवालों एवं जनगणना के सवालों के बीच अंतर को समझाना है;
- संबद्धता से परे जाकर मजदूरों को सम्पर्क करें और सुनिश्चित करें कि जनता एनपीआर से संबंधित सवालों के जवाब न दे। 'हम जबाव नहीं देंगे'। केवल जनगणना के सवालों का जवाब देना है।
- भगत सिंह और उनके साथियों के शहादत दिवस 23 मार्च को विशाल संयुक्त रैली करके अभियान का समापन करना है;
- किसानों, खेत मजूदरों आदि जैसे मेहनतकश जनता के अन्य तबकों को साथ लेकर ट्रेड यूनियनों की एकजुट कार्रवाहियों को मजबूत करें;

बेरोजगारी पर

- रोजगार के सृजन, रोजगार की गुणवत्ता, बेरोजगारी हितलाभ, काम के अधिकार, नौकरी की सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापक स्वतंत्र अभियान चलाना;
- प्रति सप्ताह 35 घंटे के काम की माँग को लोकप्रिय बनाना; सप्ताह में 5 दिन, 7 घंटे प्रतिदिन काम;
- डीवाईएफआई और एसएफआई के साथ संयुक्त कार्रवाई की संभावना की तलाश;
- डीवाईएफआई के साथ बेरोजगारी पर राष्ट्रीय सम्मेलन;
- राष्ट्रीय स्तर पर भारी लामबन्दी के माध्यम से एक दिन मनाना;

मजदूरों के तात्कालिक मुद्दों पर

- पूरे देश में व्यापक अभियान चलाकर, जिला स्तर पर जुझारु प्रदर्शन और उसी दिन गिरफ्तारी का देना;
- कार्यस्थल पर रचना में बदलाव के द्वारा हो रहे षोशण का पर्दाफाश; पी.आर. भवन की अनुसंधान टीम के सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग करें, अन्य राज्यों/स्थानों में सर्वेक्षण जारी रखें।

कामकाजी महिलाओं पर

- जून 2020 से पहले 15वीं कान्फ्रेन्स द्वारा तय की गई संरचना के अनुसार कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन;
- अप्रैल 2020 से पहले सभी यूनियनों में पर्याप्त महिला सदस्यता है तो महिलाओं की उपसमितियों का गठन;
- महिलाओं के विषेश मुद्दों – महिलाओं के साथ हिंसा और अत्याचार के खिलाफ 6 मार्च 2020 को बड़े पैमाने पर महिलाओं का 'जेल भरो' कार्यक्रम;
  - हर साल कम से कम एक बार कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तरीय कक्षाएं आयोजित करना;
  - सीटू के महिला कैडरों के ट्रेड यूनियन कौशल का विकास करना, ताकि वे संगठित क्षेत्र में यूनियनों सहित जिम्मेदारियों को उठा सकें;
  - महिला कैडरों को केवल योजना कर्मियों या महिला यूनियनों तक सीमित न रखें;

ग्रामीण मजदूरों पर

- ग्रामीण मजदूरों की स्थिति का अध्ययन करके प्रत्येक राज्य/जिले में संगठित किए जाने वाले खण्डों की पहचान करना;
- प्रत्येक खण्ड की माँगों को तैयार करें; यूनियनों के गठन का प्रयास;
- खेत मजदूरों की यूनियनों के साथ संयुक्त संघर्ष के कार्यक्रम, मिसाल के तौर पर जिला स्तरीय प्रदर्शन आदि;
- पूरे देश में एक ही दिन में खेत मजदूरों की यूनियन के साथ राज्य स्तर पर प्रदर्शन करना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीटू को मजबूत करें और अपने संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के पूरे मजदूर वर्ग को एक मजबूत जुझारु ताकत के रूप में संगठन का विकास;

आवासीय क्षेत्रों के मुद्दों पर

- शहरी क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं – मलिन बस्तियों में, राशन कार्ड, पहचान पत्र/आधार कार्ड आदि, विशेष रूप से प्रवासी व असंगठित मजदूरों, आदि के लिए और आवास, बिजली, स्वच्छता, पेयजल आदि;
- मध्यम वर्ग के फ्लैटों और कॉलोनियों में – जहाँ भी संभव हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों में सक्रिय रूप से भाग लेना, हमारे सेवानिवृत्त साथियों की सेवाओं का उपयोग करने का प्रयास;

संगठनात्मक

- सीटू केंद्र को मजबूत बनाना;
- पहले से तय लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए सदस्यता बढ़ाना;
- युवा और महिला कैडरों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्राथमिक इकाई स्तर तक देश भर में सीटू कैडरों का राजनीतिक–वैचारिक स्तर विकसित करना।
- मौजूदा अखिल भारतीय फेडरेशनों को मजबूत करना, मौजूदा राष्ट्रीय समन्वय समितियों के कामकाज में सुधार और वस्त्र, परिधान, ऑटोमोबाइल कम्पोनेन्ट निर्माण, प्रतिरक्षा के ठेका मजदूरों में राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए समन्वय समितियों का गठन करना;

राज्य/औद्योगिक फेडरेशनों की कमेटियाँः

- केंद्र द्वारा भेजी गई रिपोर्टिंग के बिंदुओं एवं अन्य दस्तावेजों सहित
- अध्यक्ष के संबोधन और महासचिव की रिपोर्ट का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करें और इसे सीटू की सबसे निचली स्तर की कमेटियों के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने के लिए छपवायें;
- प्रत्येक राज्य में कम से कम 50 और फेडरेशनों में जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक, 2020 के अंत तक राजनीतिक एवं वैचारिक रूप से सुसज्जित कैडर विकसित करना;
- सभी राज्यों की कमेटियों को पीआर भवन के लिए अपने बकाया का पूरी तरह भुगतान करना चाहिए ताकि कम से कम कक्षाओं की फीस में आंशिक रूप से कमी लाने के लिए एक कोष बनाने में मदद मिल सके;
- राज्य/औद्योगिक फेडरेशन स्तर की कक्षाओं को नियमित रूप से प्रत्येक स्तर के कैडरों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना चाहिए;
- हिंदी भाषी क्षेत्र' में सीटू की राज्य कमेटियों को विशेष रूप से कैडरों के राजनीतिक–वैचारिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए;
- 2020 में 1 करोड़ सदस्यता के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सदस्यता और उसकी ठोस योजना पर चर्चा करने के लिए जिला और सेक्टर स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन करें; राज्य केंद्र, प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे;
- सभी राज्य कमेटियाँ परिवहन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य कमेटी एक औद्योगिक क्षेत्र को चिन्हित करे और मजदूरों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करें; काम के लिए उपयुक्त कैडर आवंटित और प्रशिक्षित करें;
- हमारे सभी संबद्ध यूनियनों की कमेटियों की एक वर्ष में कम से कम 4 बार बैठकें करना सुनिश्चित करें;
- हमारे सभी यूनियनों तक सीटू साहित्य की पहुँच के लिए योजना और तंत्र स्थापित करें;
- जमीनी/कार्यस्थल/कारखाना स्तर पर मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत करने के लिए सचेत प्रयास हों;
- वर्गीय मंच से सभी प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न और सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ संघर्ष को तेज करें;
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर मजदूरों व किसानों की संयुक्त कार्रवाइयों को विकसित और मजबूत करें;
- दूसरे उद्योगों में संघर्ष, मेहनतकश जनता एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के प्रति एकजुटता की कार्रवाहियों को मजबूत करें;

अध्यक्षीय भाषण से

सीटू के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में हम अपने प्रयासों की जाँच करें, जैसा कि संविधान में वर्णित है कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज को बदलकर सभी प्रकार शोषण को समाप्त करना।

हमारे देश में, मजदूर वर्ग, फासीवादी दृष्टिकोण के साथ नवउदारवादी और निरंकुश हमलों की जद में है; और उन्हें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग इत्यादि के आधार पर विभाजित करने के प्रयास मुनाफे को अधिकतम करने के लिए शासक वर्गों की खेल योजना का हिस्सा है जबकि पूँजीवादी व्यवस्था दुनिया भर में खुद के एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। पूँजीवादी व्यवस्था मानवता की समस्याओं का समाधान खोजने में असमर्थ है। नवउदारवाद मौत के अंत में पहुँच गया है, लेकिन जब तक मजदूर वर्ग इसे विस्थापित नहीं कर देता, तब तक यह खुद से ही ध्वस्त नहीं होगा।

कई देशों में मजदूर अपनी आजीविका और कड़े संघर्षों से हासिल अधिकारों पर हमलों का विरोध कर रहे हैं। इतने सारे देशों में एक ही तरह की माँगों पर संघर्ष पहले कभी नहीं हुआ। आईएलओ ने कहा है कि दुनिया के 11 क्षेत्रों में से 7 में मजदूर एक ही समय पर संघर्ष पर थे। चिली, फ्रांस, हैती, इराक, ईरान आदि में लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं।

जैसे–जैसे नवउदारवाद अपरिहार्य साबित हुआ, पूँजीवाद तेजी से बदनाम हो रहा है, जनता, विशेषकर युवा, विकल्प खोज रहे हैं। वे तेजी से समाजवादी विचारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

इसे रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी (आईएफसी) और अमेरिकी साम्राज्यवाद चरम दक्षिणपंथी और विभाजनकारी ताकतों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वे लोगों को धर्म, क्षेत्र, रंग, भाषा, लिंग आदि के आधार पर आपस में लड़वा सकें और उनका ध्यान उनके दुखों और शोषणकारी व्यवस्था के वास्तविक कारणों से हटा सकें। हमारे देश में बीजेपी, आईएफसी और अमरिकी साम्राज्यवाद की कठपुतली की तरह उनके इरादों के लिए काम कर रही है। कई देशों जैसे वेनेजुएला, बोलीविया, ब्राजील, इराक, ईरान आदि में जनता, अपने देशों में अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों से लड़ रही है।

हमें मजदूरों को अपनी तात्कालिक माँगों का राष्ट्रीय नीतियों के साथ जुड़ाव और वैश्विक मजदूर वर्ग के हिस्से के रूप में इन हमलों के तहत मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की एकजुटता के विकास के बारे में समझना और समझाना होगा; और संगठन पर कोझीकोड दस्तावेज के अनुसार हमारी सोच और कार्य को पुनःगठित करना होगा।

हमें एकजुट मजदूर वर्ग की अंतर्निहित ताकत का एहसास करना होगा। 'हम क्या कर सकते हैं?' जैसे प्रश्न के स्वर और एक व्यक्ति की लाचारी को 'हम क्या नहीं कर सकते हैं?' से बदल दिया जाना चाहिए?

इसे हमारी सभी कमेटियों के कामकाज को न्यूनतम स्तर तक पुनर्जीवित करके और हमारे सभी कैडरों को वैचारिक रूप से पुनः तैयार करके प्राप्त किया जा सकता है। इस कान्फ्रेन्स में सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के अपने संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए, नीतियों को बदलने के संघर्षों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीतियों और कार्रवाहियों पर चर्चा और निर्णय करना होगा।

प्रस्ताव

फ्रांस के संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता

23–27 जनवरी, 2020 को चेन्नई में आयोजित सीटू की यह 16वीं कान्फ्रेन्स फ्रांस के रेल और परिवहन कर्मचारियों का क्रांतिकारी अभिवादन करता है, जो 5 दिसंबर 2019 से हड़ताल पर हैं। यह सम्मेलन भारत के मजदूर वर्ग की ओर से फ्रांस के हड़ताली कर्मचारियों के साथ एकजुटता का इजहार है।

प्रतिक्रियावादी मैक्रोन सरकार द्वारा 'पेंशन सुधारों' के नाम पर पेंशन नीति में किये बदलावों को वापस लेने की माँग को लेकर फ्रांसीसी रेल और सड़क परिवहन कर्मचारी पिछले 50 दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार ने मौजूदा विभिन्न प्रकार की 42 पेंशनों को एक में समायोजित करने का निर्णय लिया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पेंशन के तहत लाभों में भारी कमी आ जाएगी। मजदूरों को अधिक वर्षों तक काम करना होगा, लेकिन पेंशन कम ही मिलेगी। सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने पर भी विचार कर रही है, जिसका फ्रांस के मजदूर कड़ा विरोध कर रहे हैं।

हालांकि हड़ताल का आह्वान रेल और सड़क परिवहन कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा दिया गया था, लेकिन नर्सों, वकीलों, पुलिस वालों और अन्य सहित मजदूरों और कर्मचारियों के कई अन्य तबके भी 5 दिसंबर और 9 जनवरी को हड़ताल में शामिल हो गये। देश भर के विभिन्न शहरों में विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं। कई स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमले किये जिसमें कई लोग घायल हो गए।

2017 से मैक्रोन सरकार की 'सुधार' की नीतियों ने, फ्रांस में कड़े संघर्षों के माध्यम से हासिल मजदूरों के अधिकारों और कल्याणकारी लाभों में कटौतियाँ करने के रुप में हमले किये हैं। इससे उन लोगों में असंतोष पैदा हुआ है जो बड़े संघर्षों के तौर पर सामने आ रहा है। एक वर्ष से अधिक समय से 'पीली जेकेट' आंदोलन जारी है। नवंबर 2018 से, हर हफ्ते के अंत में फ्रांस में पेरिस और अन्य शहरों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में जनता प्रदर्शन कर रही है। यद्यपि टैक्सों में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बाद में कई अन्य माँगों को भी शामिल किया गया। 'पीली जेकेट' भी मजदूरों के प्रदर्शनों में शामिल हुआ।

रेल और सड़क परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कठिनाइयों के बावजूद फ्रांस में जनता हड़ताल का समर्थन कर रही है। जनता के विभिन्न तबकों ने हड़ताल के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। मजदूर, विशेष रूप से यूरोप में हड़ताल को एक ऐसे संघर्ष के रूप में देखते हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ेगा। क्योंकि, डब्ल्यूएफटीयू के महासचिव जॉर्ज माव्रिकोस ने कहा है कि यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और उनके दिशानिर्देशों पर

चलने वाली सरकारें 'मितव्ययी कदमों' के नाम पर मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों और पेंशन में कटौतियां कर रही हैं और बड़े पैमाने पर निजी कोष बना रहीं हैं।

यह न केवल यूरोप के मजदूरों, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया में जहाँ भी नवउदारवादी नीतियों को लागू किया जा रहा है, मजदूर वर्ग अपनी पेंशन, वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर ऐसे हमलों का शिकार हो रहा है। पूँजीपतियों और सरकारों द्वारा जो मजदूरों के वोटों के माध्यम से सत्तासीन होते हैं, लेकिन काम बड़े कॉरपोरेट्स के लिए करते हैं, के इस तरह के हमले, वैश्विक संकट जो अभी भी एक दशक से अधिक समय से जारी है, के बाद से और भी बढ़ गए हैं। पूँजीपति मजदूरों के हितलाभों में कटौती करके अपने मुनाफे को अधिकतम करना चाहते हैं। मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्षों को मजबूत करके और संघर्षरत मजदूरों जहाँ भी वे इन हमलों से जूझ रहे हैं, के साथ एकजुटता में खड़े होकर, पूँजीपतियों को परास्त किया जा सकता है,

सीएए को रद्द करो; एनआरसी और एनपीआर को निरस्त करो

सेन्टर ऑफ ट्रेड यूनियन का 16वीं कान्फ्रेन्स उन सभी मजदूरों एवं अन्य मेहनतकशों और जनतांत्रिक हिस्सों की जनता का स्वागत करता है जिन्हाने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ बड़े पैमाने पर देशव्यापी विरोध को जारी रखा हुआ है जिसमें 8 जनवरी 2020 की मजदूरों की देशव्यापी आम हड़ताल भी शामिल है जिसमें सीएए को रद्द करने और एनआरसी और एनपीआर को निरस्त करने की माँग की आवाज को बुलन्द किया गया।

सीएए, भाजपा सरकार द्वारा भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष नींव, जो ब्रिटिश सरकार की साम्प्रदायिक विघटन की डिजाईन, साम्प्रदायिक सौगात और देश के बंटवारे के खिलाफ 40 सालों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के सघर्ष और बलिदानों का परिणाम है, पर हमला है। साम्राज्यवाद द्वारा इस प्रकार की कुख्यात षड़यंत्रकारी डिजाईन के खिलाफ कड़ा विरोध और संघर्ष आजादी के आंदोलन की जीवन रेखा थी और इस तरह की कुख्यात डिजाईन के समर्थकों के जत्थे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी ।

आजाद भारत में, सीएए पहला साम्प्रदायिक अधिनियम ब्रिटिश सरकार की धर्म के आधार पर दो राष्ट्र के सिद्धान्त के अनुरूप है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता आन्दोंलन ने कभी स्वीकार नहीं किया और "धर्मनिरपेक्षता" एवं " समानता" भारतीय संविधान की ठोस नींव वने ।

शुरूआत 2003 में वाजपेयी सरकार के समय में एन आर सी नियमों के माध्यम से नागरिकता अधिनियम और एनपीआर में एनआरसी लाया गया, 2015 में फॉरनर्स एक्ट में संशोधन, और सीएए तीसरा कदम है जिसके बाद 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2020 तक प्रत्येक घर–घर में गणना की जायेगी। ये वे कदम हैं जो संविधान को पूर्णतया आरएसएस के "हिन्दूराष्ट्र" की स्थापना के उद्देश्य की तरफ मोड़ देंगे।

सीएए, उन शरणार्थियों के नागरिकता के अधिकार पर भी हमला है, जो विभाजन से ठीक पहले या बाद में पूर्व में पाकिस्तान से आए, उनको सीएए के अन्तर्गत नई नागरिकता का पुनः सत्यापन उत्पीड़न पूर्ण सबूत पर आधारित होगा।

एनआरसी–एनपीआर के अन्तर्गत नागरिकता प्रमाणित करने की प्रक्रिया भी बड़ी संख्या में आर्थिक और सामाजिक रूप से सीमांत लोग, भूमिहीन ग्रामीण और शहरी जनता, प्रवासी मजदूर, आदिवासी, दलित और महिलाएँ जिनके पास नागरिकता साबित करने के दस्तावेज़ नहीं हों, पर गंभीर हमला है।

और उन लोगों के लिए शरणार्थी बन्दी शिविर भी बनाए जारहे हैं जिनके मांगे गए दस्तावेज संदेहपूर्ण हों या जोदस्तावेज न ज़मा कर सकें।

इसलिए यह कान्फ्रेन्स सीएए का निरसन और एनआरसी एवं एनपीआर की अस्वीकृति की मांग करता हो।

सीटू का 16वीं कान्फ्रेन्स देश के मजदूरों, सभी मेहनत कशों और जनतांत्रि अनुभाग के लोगो को एकजुट करते हुए आन्दोलन को आगे बढ़ाने का आवाहन करता है।

जम्मू और कश्मीर में जनता और मजदूरों के अधिकारों की बहाली के लिए

23–27 जनवरी, 2020 को चेन्नई में आयोजित होने वाला सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेंड यूनियन्स (सीटू) की यह 16वीं कान्फ्रेन्स, गंभीर चिंता के साथ यह दर्ज करती है;

8 जनवरी 2020 की हड़ताल

केरल

बेंगलुरु, कर्नाटक

चेन्नई, तमिलनाडु

8 जनवरी 2020 की हड़ताल

तेलंगाना

विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश

मुम्बई, महाराष्ट्र

8 जनवरी 2020 की हड़ताल

गुजरात

भोपाल, मध्य प्रदेश

भिलाई, छत्तीसगढ़

8 जनवरी 2020 की हड़ताल

असम में रेल रोको

जलंधर, पंजाब में रेल रोको

मोगा, पंजाब

कि, संसद, जम्मू–कश्मीर की जनता और उनकी विधानसभा, को दरकिनार करते हुए, भाजपानीत मोदी सरकार ने सरकारी आदेष (जी.ओ.) के माध्यम से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के तहत विषेश प्रावधानों को समाप्त कर दिया; तथा

केवल 2 दिनों में, 5–6 अगस्त 2019 को, ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019'' संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। जिसके माध्यम से राज्य को भंग करके, इसे दो अलग–अलग संस्थाओं में विघटित किया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीज) के रूप में सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में ला दिया गया। स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि संविधान की अनुसूची–1 के तहत एक राज्य को भंग कर दिया गया है। 'एकात्मक; भारत की ओर बढने की दिशा में यह भारतीय संविधान के संघीय चरित्र पर एक गंभीर हमला है।

पहले से ही और उसके बाद से, पूरी घाटी पर ताला जड़ दिया गया है; वाणिज्यिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया; सड़कों पर सभी किस्म की आवाजाही अवरुद्ध कर दिया गया; दूरसंचार के संसाधनों को छीन लिया गया; नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, राज्य के विपक्षी दलों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं को उनके घरों में ही बन्दी बना दिया गया; राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं को श्रीनगर हवाई अड्डे पर ही हिरासत में लिया गया; जैसे कि राज्य को 'जब्त' कर लिया गया हो।

जनता के नागरिक अधिकारों पर अवैध रूप से अंकुष लगाने स्थिति अभी भी बनी हुई है; ट्रेड यूनियनों सहित जनवादी आन्दोलन, उनके लामबन्द होने और प्रदर्शन आदि अंकुश लगाया गया है; ट्रेड यूनियन अधिकारों को रौंदा जा रहा है, जबकि मजदूरों, जिनमें प्रवासी मजदूर भी षामिल हैं, गंभीर शोषण और दमन का शिकार हो रहे हैं।

सीटू का यह 16वाँ सम्मेलन जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन क्षेत्र में ट्रेड यूनियन आन्दोलन सहित जनवादी आन्दोलन की अनुमति देने, सभी तरह की नागरिक स्वतंत्रता और ट्रेड यूनियन अधिकारों की बहाली के साथ सामान्य स्थिति की तत्काल बहाली की माँग करता है।

सीटू का यह 16वाँ सम्मेलन पीड़ित मजदूरों और जम्मू एवं कश्मीर के की जनता के साथ एकजुटता में खड़े होने और जम्मू एव कश्मीर में ट्रेड यूनियन अधिकारों सहित सामान्य स्थिति की बहाली के लिए एकजुट जनवादी आंदोलन करने के लिए भारत के मजदूर वर्ग का आह्वान करता है।

क्रेडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट से

1. आयु समूहः कुल 2,000 प्रतिनिधियों में से 745 प्रतिनिधि पहली बार सीटू सम्मेलन में भाग लेने के बावजूद, केवल 16 प्रतिनिधि 30 साल से नीचे थे और 95 प्रतिनिधि 71 वर्ष से ऊपर के समूह के थे; और उनमें से 176 30–40 वर्ष के बीच के थे; 535 के 41–50 वर्ष के बीच के; 643 51–60 वर्ष के बीच के; और 453 61–70 के बीच के आयु समूह के थे जो सम्मेलन की उच्च आयु संरचना को दर्शाता है।

2. पूरा वक्ती और कामकाजी प्रतिनिधिः 737 पूरावक्ती हैं और 155 खदानों और कारखानों में काम करने वाले प्रतिनिधि, 97 कार्यालयों से, 171 सेवा क्षेत्र के कर्मचारी; 232 योजना मजदूर, 193 अन्य संगठित क्षेत्रों से और शेष अन्य क्षेत्रों से थे। उनमें से 350 सार्वजनिक क्षेत्र से, 265 निजी संगठित क्षेत्र से और 74 सहकारी क्षेत्र से थे।

निर्वाचित निकायः 85 प्रतिनिधि प्रथम स्तरीय स्थानीय निकायों के सदस्य, 36 जिला स्तर के निकायों के सदस्य, 6 राज्य विधानसभाओं और 1 संसद के सदस्य चुने गए सदस्य थे।

यूनियनों की सम्बद्धता को मंजूरी दी

जाँच के बाद, सम्मेलन ने कुल 33 यूनियनों की 8,125 सदस्यता के साथ संबद्धता को मंजूरी दी; – **असमः** 1 यूनियन – 153 सदस्यों; **छत्तीसगढ़ः** 2 – 141; **हरियाणाः** 2 – 312; **झारखंडः** 2 – 431; **कर्नाटकः** 1 – 221; **केरलः** 10 – 4,122; **मध्य प्रदेशः** 4 – 296; **महाराष्ट्रः** 4 – 1,500; **राजस्थानः** 1 – 200; **तमिलनाडुः** 2 – 489; **तेलंगानाः** 2 – 36; **उत्तर प्रदेशः** 1 – 120; **पश्चिम बंगालः** 1 – 104।

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स का आह्वान

● वर्गीय एकता को गहरा और व्यापक बनाओ ● कामकाजी जनता और समाज पर हमलों का विरोध करो ● आगे बढ़ने के लिए शासक वर्ग की बाधाओं को चुनौती दो

तपन सेन

सीटू की 16वाँ कान्फ्रेन्स 27 जनवरी 2020 को संपन्न हुई है, जिसमें जनता के जीवन और आजीविका, उनके अधिकार और जनता की एकता पर शासक वर्ग के बर्बर हमलों के विरोध में एकजुट संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए, समग्र रूप से मेहनतकश वर्ग की एकता को व्यापक बनाते हुए और एकजुट करने का आह्वान किया गया है।

कान्फ्रेन्स ने स्पष्ट शब्दों में सामूहिक रूप से कल्पना की है कि आज के समय की जरूरत है कि संयुक्त संघर्षों को राष्ट्रीय और कार्यस्थल दोनों स्तरों पर प्रतिरोध के स्तर तक ऊँचा किया जाए और इसके लिए जमीनी स्तर पर मजदूरों की चेतना को बढ़ाने के लिए एकता को मजबूत करना होगा।

कान्फ्रेन्स ने यह भी उल्लेखित किया है कि व्यापक नियोक्ता समर्थक कानूनों के माध्यम से ट्रेड यूनियनों के द्वारा संगठित करने और सामूहिक कार्रवाई के अधिकार पर एक आभासी प्रतिबन्ध लगाने के लिए शासक वर्ग के आक्रामक एवं अत्याचारपूर्ण कदमों और इन निषेधात्मक बाधाओं का सामना करने के लिए, निरंतरता के साथ राष्ट्रीय एवं कार्यस्थल दोनों स्तरों पर संगठित एवं एकजुट कार्रवाहियों के माध्यम से इसकी अवहेलना करना है। और इसके लिए कार्यस्थल स्तर तक मेहनतकश तबकों की एकता को मजबूत करने और विस्तार करने की भी जरुरत है।

यह कान्फ्रेन्स सीटू की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में हुई है, जो देश में पहले राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र के गठन के शताब्दी वर्ष के साथ भी मेल खाता है। पचास साल पहले, सीटू की स्थापना, पूरे समाज को हर तरह के शोषण से मुक्ति के काम को उसके संविधान में सुनिश्चित किया गया था।

सीटू की स्थापना कान्फ्रेन्स ने 'एकता और संघर्ष' का स्पष्ट आह्वान किया था; पिछले पाँच दशकों के दौरान, ट्रेड यूनियन आंदोलन के एकजुट मंच को, शोषण के खिलाफ लगातार संघर्ष के माध्यम से लगभग सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों को शामिल करते हुए निरंतरता के साथ व्यापक और विस्तारित किया गया था।

इस समृद्ध अनुभव के गहन आत्म–आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, कान्फ्रेन्स सामूहिक रूप से इस एहसास पर पहुँचा है कि ट्रेड यूनियनों की इस एकता को और अधिक प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है और जमीनी स्तर पर संबद्धता से उपर उठकर मजदूरों की मुक्कमल एकता में परिवर्तित करना होगा। और इसके लिए मजदूरों और देश भर में मेहनतकश जनता के बीच शोषणकारी पूँजीवादी व्यवस्था और उसी को बढ़ावा देने वाली राजनीति के खिलाफ संघर्ष का संदेश देने के लिए बहुत व्यापक और गहरी पहुँच की आवश्यकता है।

वर्तमान सत्तावादी व्यवस्था के तहत आज के समय में उभरती चुनौतियों की पृष्ठभूमि में गतिविधियों और सीटू के संगठन पर आत्म–आलोचनात्मक विचार–विमर्श की प्रक्रिया में सम्मेलन, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर इसके विभाजनकारी और विकृत तंत्र के बारे में जोर दिया। मेहनतकश लोगों की व्यापक एकता और न पहुँचे क्षेत्रों को कवर करने के लिए जागरूक संगठनात्मक समेकन और विस्तार की दिशा में हमारे काम को पूरी तरह से पुर्नगठन करने की आवश्यकता है।

हम अतिरिक्त रुप से असामान्य स्थिति के दौर में हैं जैसा कि कान्फ्रेन्स ने साफ तौर पर उल्लेखित किया है। सत्तारूढ़ पूँजीवादी भूस्वामी वर्ग के पूर्ण संरक्षण के साथ, वर्तमान भाजपा सरकार समाज में विभाजन, टकराव और विघटन की अपनी व्यापक परियोजना पर चल रही है, और फासीवादी सत्तावाद की ओर बढ़ते हुए नवउदारवादी पूँजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। संकट के दौर में देशी–विदेशी कॉरपोरेट्स के हाथों राष्ट्रीय सम्पत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को लुटाने का काम के किया जा रहा है और मेहनतकश जनता की आजीविका और उनके अधिकारों पर हमला कर रही है।

कान्फ्रेन्स ने अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर इसकी सभी अभिव्यक्तियों के द्वारा हमारे समक्ष मौजूद तमाम चुनौतियों के बारे में व्यापक समझ की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका सभी मोर्चों पर एक साथ मुकाबला करना होगा। इस समझ को मजदूरों और जनता के बहुमत के बीच विकसित करना है।

इस मामले में, कान्फ्रेन्स ने हमारे दृष्टिकोण और कार्य में गंभीर कमियों और कमजोरियों की व्यापकता में पहचान की है, जिसके कारण गहन संघर्ष, आंदोलन, लामबंदी और संबंधित संगठनात्मक गतिविधियों की निरंतरता के साथ स्वतंत्र पहल एवं संयुक्त मंच दोनों पर कमी रहती है। इस दौरान बर्बर शोषक प्रणाली और उन्हें बढ़ावा देने वाली राजनीति के बारे में मजदूरों की चेतना बढ़ाने में वांछित परिणाम नहीं आये हैं कि वे अपने असली दुश्मन की पहचान कर सके। और चेतना की कमी ने उन्हें शासक वर्ग की दकियानूसी रणनीति का आसान शिकार बना दिया।

कान्फ्रेन्स ने दोहराया कि वर्तमान व्यवस्था से लड़ने के लिए मजदूर वर्ग के आंदोलन को इन सभी मोर्चों – नवउदारवाद, सांप्रदायिकता और अधिनायकवाद सभी पर गठबंधन बनाने के लिए अग्रणी भूमिका निभानी होगी। यह एक या दूसरा नहीं हो सकता। किसी खास नेता या मंत्री के खिलाफ हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं हो सकती। इसकी नीतिगत बनावट और समाज पर इसके प्रभावों के खिलाफ इसे निर्देशित किया जाना चाहिए। संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं को, इस समझ को जमीनी स्तर पर गहन अभियान के माध्यम से मजदूरों के बीच बड़े पैमाने पर ले जाने की पहल करनी चाहिए। सिर्फ यही अकेले मजदूरों और मेहनतकश जनता को उनके असली दुश्मन की पहचान करायेगा और उस दुश्मन से लड़ने के लिए उनको सभी की एकजुट शक्ति में एक साथ लेकर आएगा। इसके लिए कोई पगडंडी नहीं है।

जो भी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो मजदूर वर्ग के पास उससे लड़ने और शासक वर्ग के हमलों को परास्त करने की जबरदस्त क्षमता है बशर्ते कि उचित संगठनात्मक और आंदोलनात्मक पहल की जाये।

मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरा स्टील, बीईएमएल, ब्रिज एंड रूफ, सीईएल आदि सहित कम से कम दस सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री पूरी करने का फैसला किया, लेकिन राष्ट्रीय और संस्थान के स्तर पर मजदूरों के एकजुट संघर्ष के कारण ऐसा नहीं कर सकी। रक्षा उत्पादन के मजदूरों ने अभी तक जुझारु देशव्यापी हड़ताली कार्रवाई के माध्यम से आयुध कारखानों के निगमीकरण के कदम को हालांकि अस्थायी रूप से रोक रखा है। योजना मजदूरों ने निरंतर लड़ाई के द्वारा अभी तक केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे कि आंगनवाड़ी, मध्यान्ह–भोजन आदि के एकमुश्त निजीकरण के कदम का विरोध करते हुए पकड़कर रखा है। कई अन्य उदाहरण भी हैं। केंद्र में दूसरी बार मोदीनीत भाजपा सरकार के गठन के लगभग तुरंत बाद देश भर में शुरू हुई मजदूरों के संघर्ष की श्रंखला से यह फिर से साबित हुआ, जो अंततः 8 जनवरी, 2020 को मेहनतकश जनता की सबसे बड़ी आम हड़ताल में बदल गया। इस अंतर्निहित क्षमता के साथ मजदूर वर्ग में लड़ने की वृत्ति ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसके आधार पर हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं।

इस कान्फ्रेन्स में, आर्थिक प्रबंधन और शासन में हर तरह की विफलता को ढ़ांकने के कुत्सित इरादे से, आम नागरिकों और लोकतांत्रिक संस्थानों एवं संवैधानिक मूल्यों पर भाजपा सरकार के हताशापूर्ण, बर्बर और विभाजनकारी हमलों के खिलाफ विशेष रूप से आम जनता, छात्रों और युवाओं में भड़के तीखे प्रतिरोध की घटना पर गौर किया गया है। वास्तव में, सरकार के कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के कारण जनता के जीवन और आजीविका के अकल्पनीय दुःख और संकट के साथ–साथ, स्पष्ट रूप से फासीवादी और अधिनायकवादी इरादे के साथ संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और यूएपीए में क्रूर संशोधन करने के बाद सीएए/एनपीआर/एनआरसी के नाम पर मोदी शासन की सर्वाधिक बर्बरतापूर्ण कवायद ने उसके खिलाफ स्वतः स्फूर्त आंदोलन के उभार में एक भूमिका निभाई है।

कान्फ्रेन्स ने सामूहिक रूप से समझ बनायी है कि स्वतःस्फूर्त विरोध की इन धाराओं को इस सत्तावादी एवं विभाजनकारी शासन के खिलाफ जनता के संगठित प्रतिरोध एवं संघर्ष के रास्ते पर जुटाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ इसके साथ जनता की आजीविका के मुद्दों को जोड़ते हुए, और आरएसएस के नेतृत्व में सत्तारूढ़ व्यवस्था के वर्तमान विकृत और विखंडन के इरादों को उजागर करते हुए एकजुट करना होगा। इस जिम्मेदारी को, मजदूर वर्ग के आंदोलन को अपने उपर लेकर, उस दिशा में अपनी पहल और काम को पुर्नगठित करना पड़ेगा।

जैसा कि कान्फ्रेन्स ने बताया है कि यह बिना कारण के नहीं है कि वर्तमान भाजपा सरकार सभी श्रम कानूनों को व्यापक रूप से मालिकान के पक्ष में बदलने के माध्यम से, गुलामी स्थितियों को मजदूरों पर थोपने और एक वर्गीय संगठन के रूप में उनकी

सामूहिक हस्तक्षेप की क्षमता को कमजोर करने के लिए प्रतिबद्ध है। चालू आर्थिक संकट के दौर में, यह पूँजीवादी वर्ग की सेवा और सुविधा के लिए श्रम लागत को और भी कम करने के लिए और पूँजीपति वर्ग एवं शासन में उनके राजनीतिक एजेंटों के अन्याय और लूट के खिलाफ, समाज के सबसे संगठित वर्ग को, हस्तक्षेप करने की उसकी क्षमता को कमजोर करना है।

इसलिए कान्फ्रेन्स सामूहिक रूप से यह समझ बनायी है कि मजदूर वर्ग का संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है।

आर्थिक नीति के हर मोर्चे निजीकरण, राश्ट्रीय संपत्तियों की बिक्री, विदेषी पूंजी और उसके देशी साझादारों के पक्ष में अर्थव्यवस्था की स्वदेशी उत्पादन क्षमता को नष्ट करने आदि पर तथा जनता की कल्याणकारी व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों में भारी कटौती, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य–वृद्धि को बढ़ावा देने की षासक वर्ग की हर विकृत कार्रवाई के खिलाफ संगठित, और एकजुट प्रतिरोध तैयार करना है।

मजदूरों की सामूहिक कार्रवाइयों को अवैध करने के इरादे से, कार्यस्थलों पर आभासी गुलामी की स्थितियों को लागू करने और श्रम अधिकारों और ट्रेड यूनियन अधिकारों को समाप्त करने के लिए किए जा रहे अत्याचारपूर्ण उपायों और उन विकृत नीति शासन के खिलाफ मजदूर वर्ग और उनके संगठनों द्वारा, संघर्ष का वर्तमान चरण भी संगठित एकजुट अवहेलना का होना चाहिए।

मजदूर वर्ग के संघर्षों का विस्तार एवं व्यापक, देश की उत्पादक आबादी के अन्य क्षेत्रों, किसानों और खेत मजदूरों के बीच भी हो रहा है; मजदूरों–किसानों की एकता, संकट में फंसी नवउदारवादी व्यवस्था की देन अन्याय और दुखों के खिलाफ लड़ाई में समाज के अन्य तबकों जिसमें छात्र और युवा शामिल हैं को आकर्षित करने का काम करेगी।

कान्फ्रेन्स ने यह भी बताया कि शासक वर्ग द्वारा आर्थिक नीति की व्यवस्था में वही नीति अपनायी जा रही है जो राजनीतिक मंच पर, शासन में शामिल उनके चरम दक्षिणपंथी राजनीतिक एजेंटों द्वारा समाज में चलायी जा रही उनकी विभाजनकारी योजना जो संकट के बीच खुद को बनाए रखने के लिए अभिन्न रणनीति का हिस्सा है। जनता की एकता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने वाले संविधान के बुनियादी सिद्धांतों, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी क्रूर हमले हो रहे हैं। मजदूर वर्ग का आंदोलन, उनकी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में, बड़े पैमाने पर मेहनतकष जनता के साथ मिलकर इन हमलों और साजिशों से लड़ने के लिए एकजुट हुआ है।

एक अतिआवश्यक तात्कालिक कार्य के रूप में, कान्फ्रेन्स ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए गहनता से घर–घर जाकर और कार्यस्थल के स्तर पर फरवरी–मार्च में अभियान चलाने की पहल करते हुए, मजदूरों और उनके परिवारों का, जवाब न देने और एनपीआर गणना प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने का आह्वान किया। इस अभियान का समापन 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस पर, सांप्रदायिक विभाजनकारी और ठिठाईपूर्ण संविधान विरोधी कदमों के खिलाफ पूरे देश में बड़ी लामबन्दी करनी है।

एक वर्गोन्मुख ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में, अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित 16वीं कान्फ्रेन्स में सीटू ने वर्तमान दक्षिणपंथी नीति शासन द्वारा जनता पर और मजदूरों पर हर हमले के प्रतिरोध के लिए वर्ग के एकजुट संघर्षों को बढ़ाने की दिशा में अपने काम और पहल को पूरी तरह से पुनर्जीवित करके इस अवसर पर बढ़ने का संकल्प लिया। संपूर्ण तरीके से मजदूर वर्ग को एकजुट करने और मजदूरों के बीच उच्च चेतना विकसित करते हुए जिससे वे अपने वास्तविक दुश्मनों की पहचान कर सकें और सत्ता द्वारा गहराते संकट के बीच शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखने के वास्ते पैदा की जा रही सभी बाधाओं को दूर करने और उन पर काबू पाने का संकल्प लिया।

और इस तरह के कार्य के लिए तैयार करने के लिए, हमारी संगठनात्मक समझ और प्रथाओं की पुर्नसंरचना करना आज के समय में तुरन्त आवष्यक है। प्रतिरोध की आवश्यकता है कि प्रत्येक क्षेत्र–विशिष्ट हमले पर हमारी प्रारंभिक संगठनात्मक पहल में अधिक सूक्ष्म–स्तरीय ध्यान केंद्रित करना होगा और एकजुट प्रतिरोध के साथ–साथ क्षेत्रीय/उद्योग/संस्थान के स्तर पर प्रतिरोध का माहौल विकसित करना होगा। सीटू का आह्वान है कि जिन तक न पहुँचे उन तक पहुँचना, मुद्दों को नीतियों के साथ जोड़ना और इस तरह की नीतियों को बढ़ावा देने वाली राजनीति पर्दाफाश करने को आत्मसात करने, समझने और उस दिशा में क्रियान्वित करने के लिए होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक सम्पूर्ण सीटू को अपने संवैधानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खुद को राजनीतिक, वैचारिक और संगठनात्मक रूप से तैयार करना चाहिए। – स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स का आह्वान यही है।

8 जनवरी 2020 – मजदूरों की आम हड़ताल

मजदूरों की यह देशव्यापी आम हड़ताल पिछली हड़तालों की तुलना में और भी सघन थी। केरल, असम, बिहार, ओडिशा, गोवा आदि में पूर्ण बंद था और कई औद्योगिक शहरों और केंद्रों में बंद जैसी स्थिति थी। लगभग 25 करोड़ मजदूरों, कर्मचारियों और जनता के अन्य तबकों ने हड़ताल की और लामबंदी में हिस्सा लिया।

किसानों और खेतिहर मजदूरों के संगठनों ने ग्रामीण बंद का आह्वान किया और इसके लिए व्यापक स्तर पर अभियान भी चलाया। देश के कई हिस्सों में ऐसे ग्रामीण बंद सफल रहे।

छात्र, युवा और महिला संगठनों ने भी हड़ताल के अभियान के दौरान और हड़ताल के दौरान सक्रियता से शिरकत की। हड़ताल से पहले उभरे ज्वलंत मुद्दे –सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ लोगों में व्याप्त रोष ने देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई में एक नया आयाम जोड़ा, और सरकार की जनविरोधी, मजदूर विरोधी, राष्ट्रविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट श्रमिक वर्ग आंदोलन के आह्वान के प्रति लोगों के समर्थन को आकर्षित किया।

इस हड़ताल की महत्वपूर्ण विशेषता मजदूरों और हड़ताल के समर्थकों की भारी लामबंदी थी जो हड़ताल के दिन देश के हर शहर और कस्बे में सड़कों पर प्रदर्शनों में दिखाई दी। इन प्रदर्शनों के माध्यम से देश की जनता ने मुद्दों पर अपने एकजुट होने और सरकार की जनविरोधी नीतियों और दमनकारी शासन के खिलाफ अपनी एकता साबित की।

देश में हजारों स्थानों पर, सैंकड़ों हजारों लोगों की भागीदारी के साथ विशाल प्रदर्शन, रेल रोको और सड़क रोको कार्यवाहियां आयोजित की गईं। कई राज्य सरकारों ने हड़ताल के दिन ट्रेड यूनियन नेताओं के आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया; प्रदर्शनों और बैठकों पर प्रतिबंध लगाया गया; धारा 144 लगाई गई और वर्कर्स और जनता को डराने के लिए सशस्त्र पुलिस बलों की विशाल टुकड़ियां तैनात की और हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां भी कीं। फिर भी, मजदूरों और जनता ने सभी प्रतिबंधों और धमकियों को धता बताते हुए प्रदर्शनों मे भाग लिया।

असम में सीटू और एसएफआई नेताओं सहित दो हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल में श्रमिकों और जनता के अन्य तबकों ने तष्णमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हड़ताल के विरोध में धमकी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को हड़ताल तोड़ने वालों के रूप में तैनाती को खारिज करते हुए भारी संख्या में हड़ताल में हिस्सा लिया। गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में मजदूरों ने उनकी राज्य सरकारों द्वारा हड़ताल में भाग लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ – साथ अन्य धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। गोवा में, भाजपा सरकार ने दुकान मालिकों को अपनी दुकानों को बंद न करने के लिए डराने–धमकाने की कोशिश की और ट्रांसपोर्टरों और परिवहन कर्मचारियों को वाहनों को चलाने के लिए मजबूर किया। लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, राज्य के लोगों ने पूर्ण बंद लागू किया। मजदूर और जनता सड़कों पर निकल आए, कई राज्यों में धारा 144 को की परवाह न करते हुए बड़े पैमाने पर रैलियां कीं गईं।

क्षेत्रवार हड़ताल

औद्योगिक संकुल– देश भर के कई औद्योगिक संकुलों में मुकम्मल हड़ताल थी, जिसमें कर्नाटक के बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे टोयोटा, वोल्वो बसें, वोल्वो ट्रक, बॉश, आईटीसी, विक्रम (जेके) टायर्स, रीड एंड टेलर आदि में मुकम्मल हड़ताल थी। हड़ताल के कारण कर्नाटक, महाराष्ट्र, एनसीआर – दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, और पश्चिम बंगाल आदि में अधिकांश औद्योगिक संकुल बंद थे। मध्य प्रदेश में इंदौर, नीमच आदि औद्योगिक क्षेत्रों में, झारखंड में जमशेदपुर, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, राजकोट और सूरत के औद्योगिक क्षेत्रों में भी हड़ताल हुई; पंजाब में लुधियाना, जलंधर, रायकोट आदि में, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और राजस्थान में जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों आदि में आंशिक हड़ताल हुई। कई राज्यों में शॉपिंग मॉल भी बंद रहे।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र – पिछली हड़तालों की तुलना में इस हड़ताल को सार्वजनिक क्षेत्र के वर्कर्स की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। भेल की कई इकाइयों – त्रिची, रानीपेट आदि में मुकम्मल हड़ताल रही। गौरतलब है कि भेल झांसी में पूर्ण हड़ताल रही और हरिद्वार में लगभग 70 प्रतिशत हड़ताल रही। आरआईएनएल वाइज़ैग और सेलम स्टील प्लांट में पूर्ण हड़ताल थी और अन्य स्टील प्लांट में आंशिक। ओडिशा में एनटीपीसी, स्टील, नाल्को दमनजोड़ी आदि में कई

सार्वजनिक उपक्रमों में संविदा कर्मी, जो आज कुल श्रमिकों का भारी बहुमत हैं, ने पूरी तरह से भाग लिया। कोयले में हड़ताल महत्वपूर्ण थी।

बंदरगाह– काकीनाडा, तूतीकोरिन, कोचीन, मझगांव, पारादीप और कोलकाता बंदरगाह स्थायी और ठेका श्रमिकों की हड़ताल के कारण बंद थे। तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह को छोड़कर निजी बंदरगाहों सहित सभी बंदरगाह बंद थे। 100 प्रतिशत हड़ताल के कारण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को बंद कर दिया गया था।

डीआरडीओ– हड़ताल के कारण देश भर में रक्षा लैब्स बंद थे।

बिजली– राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा पूर्ण हड़ताल के कारण उत्तर प्रदेश सहित देश भर में उत्पादन और वितरण प्रभावित हुआ।

सड़क परिवहन– देश में लगभग 3.5 करोड़ सड़क परिवहन श्रमिकों, जिसमें स्थानीय परिवहन जैसे ऑटो आदि शामिल हैं, ने हड़ताल में भाग लिया। परिवहन मालिकों के एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का समर्थन किया। बिहार में भी राज्य परिवहन पूरी तरह से प्रभावित था जिसमें हड़ताल में ऑटो कर्मचारी भी शामिल थे। कई राज्यों में सड़कें सुनसान थीं जो हड़ताल को प्रदर्शित कर रही थीं। मध्य प्रदेश में भी, जहाँ अधिकांश सड़क परिवहन कर्मचारी संगठित नहीं थे, उन्होंने 10 जिलों में हड़ताल में भाग लिया।

स्कीम वर्कस– देश भर के लाखों स्कीम वर्कर्स, खासकर आंगनवाड़ी कर्मचारी, मिड डे मील और आशा वर्कर हड़ताल, प्रदर्शन और धरने में शामिल हुए।

मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव्स– देषभर में कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक श्रमिकों द्वारा हड़ताल की गई थी। कई राज्यों में उन्होंने हड़ताल में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को संगठित किया।

आईटी– इस बार आईटी कर्मचारी, न केवल आईटीईएस के कर्मचारी, बल्कि तथाकथित पेशेवर आईटी भी हड़ताल में शामिल हुए। कर्नाटक में, हड़ताल के समर्थन में बेंगलुरु में केआईटीयू (कर्नाटक आईटी/आईटीईएस कर्मचारी यूनियन) द्वारा एक विशाल मोटर बाइक रैली का आयोजन किया गया था। पश्चिम बंगाल में, लगभग 35 प्रतिशत आईटी कर्मचारी हड़ताल पर थे, जबकि एसडीएफ कॉल सेंटरों में हड़ताल पूर्ण थी। केरल में कोच्चि आईटी हब में, विप्रो, टीसीएस, जेरॉक्स आदि सहित अधिकांश आईटी कंपनियों ने कोच्चि इन्फोपार्क के इतिहास में पहली बार बहुत कम उपस्थिति दर्ज की। छोटे और मध्यम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियों के साथ राज्य भर के अक्षय केंद्रों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी– सरकारों की चेतावनी को अनदेखा करते हुए हड़ताल में भाग लिया। डाक, आयकर, ऑडिट व एकाउंट्स आदि में लगभग 13 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भाग लिया।

बैंक और बीमा– बैंक और बीमा क्षेत्र में पूर्ण हड़ताल थी।

दूरसंचार– कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया।

इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र के कई हिस्सों जैसे कि **निर्माण, बीड़ी, ईंट भट्ठा, ग्राम चौकीदार, गृह आधारित कामगार, घरेलू कामगार, ऑटो रिक्शा चालकों** आदि ने हड़ताल में भाग लिया, साथ ही देश भर के **बागान** मजदूरों ने भी इसमें भाग लिया। **गारमेंट** कर्मचारियों ने भी बड़ी संख्या में हड़ताल में भाग लिया।

ट्रेड यूनियन संगठनों से पार हड़ताल– पिछली हड़तालों की ही तरह, सैकड़ों हजारों श्रमिक, किसी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रति निष्ठा को भुलाकर औद्योगिक क्लस्टरों में हड़ताल में भाग लिया। उनमें से ज्यादातर किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं थे।

राज्यवार हड़तालें

केरल

केरल में, पूरे राज्य में बंद जैसी स्थिति व्याप्त थी। खेतिहर मजदूरों सहित करीब 1.6 करोड़ श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। केएसआरटीसी व अन्य सार्वजनिक परिवहन सड़कों पर नहीं थे। कोचीन

बंदरगाह पर, वल्लारपदोम कंटेनर टर्मिनल, अलुवा–कलमसेरी औद्योगिक बेल्ट, कोझीकोड औद्योगिक क्षेत्र, एसईजेड, आईटी सेक्टर आदि में पूर्ण हड़ताल थी। बिजली, जल प्राधिकरण, परिवहन में, व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों मे पूर्ण हड़ताल थी। एफएसीटी, वीएसएससी, बीएसएनएल, एचएलएल जैसे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में भी हड़ताल थी। बैंक, बीमा, सहकारी क्षेत्र, डाक, दूरसंचार, शैक्षणिक संस्थान, राज्य सरकार के कार्यालय, केंद्र सरकार के कार्यालय बंद रहे। वृक्षारोपण क्षेत्र, पारंपरिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण में पूर्ण हड़ताल रही।

त्रिवेंद्रम और सभी जिला केंद्रों पर बड़े पैमाने पर रैलियां की गईं। त्रिवेंद्रम में 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया।

500 से अधिक हड़ताल केंद्र खोले गए और हजारों और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा आयोजित हड़ताल केंद्रों पर एकत्र हुए। सभी केंद्रों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार हो रहे थे। बड़े पैमाने पर लोगों ने हड़ताल में साथ दिया।

विभिन्न पूर्व–हड़ताल अभियान कार्यक्रम जैसे राज्यव्यापी वाहन रैली, डोर टू डोर अभियान आदि का आयोजन किया गया।

कर्नाटक

इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईटीयूसी, टीयूसीसी, एआईसीसीटीयू, एचएमकेपी, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, जेएएफ, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अन्य स्वतंत्र यूनियनों के नेतष्त्व में राज्य भर में बड़े पैमाने पर हड़ताल की गई। हड़ताल को रोकने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के अलोकतांत्रिक और सत्तावादी षड़यंत्रों के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, योजना श्रमिकों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों के 1 लाख से अधिक श्रमिकों ने राज्य भर में हड़ताल में भाग लिया। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से दी गई हड़ताल के समर्थन में 50 लाख से अधिक श्रमिकों ने काम रोक दिया।

बैंगलोर शहर के, फ्रीडम पार्क में 10,000 से अधिक मजदूरों नेविरोध प्रदर्शन में भाग लिया। राज्य भर में हजारों कार्यकर्ताओं ने रैलियों में भाग लिया।

तमिलनाडु और पुदुचेरी

सभी केंद्रीय यूनियनों द्वारा आह्वनित अखिल भारतीय आम हड़ताल, तमिलनाडु में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। हड़ताल में सेलम स्टील, रानीपेट व त्रिची के भेल प्लांट्स, तूतीकोरिन पोर्ट, बीपीसीएल बॉटलिंग, भारत पेट्रोलियम, एलएंडटी, ईसीजी, नोबल टेक, जनरल इलेक्ट्रिकल्स और अषोक लीलैंड यूनिट –2 षामिल थे। एनटीसी मिलों सहित 14 कपड़ा मिलों में काम रोक दिया गया। इंजीनियरिंग उद्योग में 5,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। पूरे राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक ऑटो वर्कर्स ने हड़ताल की।

चेन्नई में पोर्ट स्ट्राइक 25 प्रतिशत थी, डिफेंस में 60 प्रतिशत, ओएफटी (त्रिची) में 55 प्रतिषत, अरावणकडु डिफेंस में 55 प्रतिशत। टीएनपीएल के 50 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मेडिकल रिप्रेसेंटिट्वस ने पूर्ण हड़ताल की। सीपीएसयू में हड़ताल लगभग पूर्ण थी। एलआईसी में 95 प्रतिशत हड़ताल हुई, बैंकिंग क्षेत्र में पूर्ण हड़ताल रही, केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा 90 प्रतिशत, और बिजली कर्मचारियों द्वारा 55 प्रतिशत रही।

एक नई कोशिश के तहत, सीटू ने जनता से आह्वान किया कि दोपहर 12 बजे से 12.10 तक '10 मिनट तक ईंजन बंद कर काम ठप्प किया जाए। आह्वान को वाहन उपयोगकर्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 16 महत्वपूर्ण जंक्शनों पर 60,000 वाहनों ने अपना इंजन बंद कर दिया। पूरे राज्य में लगभग 5 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया।

सभी जिलों के 200 से अधिक केंद्रों पर लगभग 1 लाख मजदूरों ने पिकेटिंग धरना में भाग लिया और 6,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुदुचेरी में, 13 केंद्रों में पिकेटिंग की गई और 610 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, लगभग 5 लाख श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया।

तेलंगाना

तेलंगाना में, हड़ताल सफल रही। अनुमानित 13 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। 466 केंद्रों में हड़ताल के दिन रैलियां की गईं जिनमें लगभग 1.5 लाख मजदूरों ने भाग लिया। हैदराबाद और उसके आसपास के औद्योगिक संकुल में, 2.25 लाख से अधिक श्रमिकों की भागीदारी के साथ 3,419 औद्योगिक इकाइयों में हड़ताल एक बड़ी सफलता थी। 8 बीएमएस यूनियनों ने भी हड़ताल में भाग लिया। सिंगरेनी कोयला खदानों में, 65 प्रतिशत नियमित और ठेका श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। तेल क्षेत्र में बीपीसीएल और आईओसीएल की हड़ताल 100 फीसद थी। एचपीसीएल में हड़ताल आंशिक थी। डिफेंस लैब्स (डीआरडीओ) में 90 प्रतिशत और बीडीएल में 40 प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया।

राज्य में औद्योगिक असंगठित श्रमिको की संख्या 5.5 लाख हैं, जिनमें से 8 जिलों में 3274 औद्योगिक इकाइयों में 2 लाख से अधिक श्रमिक हड़ताल में शामिल हुए।

आंध्र प्रदेश

अनुमानित 15 लाख मजदूरों और कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। हड़ताल के दिन ट्रेड यूनियनों की संयुक्त रैलियों का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों और स्वतंत्र रूप से सीटू समितियों द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 2.5 लाख मजदूरों ने भाग लिया।

वि,ाखापत्तनम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में हड़ताल विजाग स्टील प्लांट में थी – जिसमे 94.78 प्रतिशत स्थायी श्रमिकों, 100 प्रतिशत ठेका श्रमिक; 100 प्रतिशत एचपीसीएल ठेका श्रमिक, 52 प्रतिशत हिंदुस्तान शिप यार्ड, 42 प्रतिशत भेल; डॉकयार्ड में 20.54 प्रतिशत, 44 प्रतिशत पोर्ट व 22 प्रतिशत बीडीएल की भागीदारी रही। निजी उद्योगों में, सीटू यूनियनों ने श्रीकाकुलम, विजयनगरम और अन्य जिलों में हड़ताल की।

अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेतिहार मजदूर यूनियन ने 22,000 की भागीदारी के साथ लगभग 200 स्थानों पर ग्रामीण बंद का आयोजन किया। कई अल्पसंख्यक संगठनों ने हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया और रैलियों में भाग लिया।

हड़ताल पूर्व तैयारी अभियान में विजयवाड़ा में राज्य कन्वेंशन के अलावा जिला, मंडल और शहर स्तर के कन्वेंशन शामिल हैं, यूनियनों की जनरल बॉडी बैठकें, गेट मीटिंग, 150 केंद्रों पर चल रहे दो राज्य स्तरीय जत्थे, पैम्फलेट आदि शामिल है।

संसद में

केंद्रीय बजट और केरल के साथ भेदभाव के खिलाफ संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करते वामपंथी सांसद

राज्यों से

कनार्टक

20,000 मिड–डे–मील वर्कर्स का बैंगलोर के लिए मार्च

कनार्टक राज्य मिड–डे–मील वर्कर्स यूनियन सीटू ने बीजेपी की सरकार के मिड–डे–मील के निजीकरण करने के खिलाफ वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों के लिए 3 फरवरी 2020 से अनिश्चित कालीन हड़ताल और फ्रीडम पार्क बैंगलोर में धरने का आहवान किया। बी जे पी सरकार ने फ्रीडम पार्क में धरने की मंजूरी नहीं दी और वहां धारा 144 लगा दी। वर्कर्स को बैंगलोर आने से रोकने की कोशिशें की गई, पुलिस द्वारा रोकने की हर संभव कोशिशे की गई, नेताओं को नजरबंद किया गया। सीटू की राष्ट्रीय उप प्रधान, राज्य की प्रधान और मिड–डे–मील वर्कस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड वारालक्ष्मी के नेतृत्व में 20,000 मिड–डे–मील वर्कर्स बैगलोर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए।

सीटू की मिड–डे–मील वर्कर्स यूनियन ने सरकार को पहले ही सूचित कर दिया कि 3 फरवरी 2020 से वर्कस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाऐगें। इस धरने को रोकने के लिए पुलिस ने सेक्शन 144 लगा दिया और कॉमरेड वारालक्ष्मी व अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया आगे जाने से रोकने की स्थिति में वर्कर्स ने रेलवेस्टेशन पर ही धरना शुरू कर दिया। प्रशासन को वारालक्ष्मी को रिहा करने के लिए मजबूर किया गया। इसके पश्चात राज्य के मंत्री और प्रशासकीय अधिकारी धरना स्थल पर आए और आश्वासन दिया कि मिड–डे–मील का निजीकरण नहीं किया जाएगा। और बाकी मांगों के बारे में 13 फरवरी 2020 को सरकार और यूनियन के बीच बात चीत की जाएगी।

इस आश्वासन के बाद धरना हटा दिया और हड़ताल समाप्त कर दी गई।

उद्योग

बैंकिंग

बैकों में मुकम्मल हड़ताल

यूएफबीयू के आहवान पर 31 जनवरी और 1 फरवरी 2020 को बैकों का काम पूरी तरह बंद रहा। बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस हड़ताल को सफल बनाया। 1 नवम्बर 2017 से लम्बित वेतन समझौते को शीघ्र से करने की मांग पर यह हड़ताल हुई ।बैंक कर्मचारियों के हड़ताल में शिरकत करने से ए टी एम भी प्रभावित हुए।

सीटू के 16 वें सम्मेलन के 25 जनवरी 2020 को बैंकों के हड़ताली कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ एक जुटता का एक प्रस्ताव पारित किया। हड़ताली कर्मचारियों और अधिकारियों ने बैंको की पिकेटिंग की, गेटों पर जुलूस निकाले और रैलियां व बैठकें भी कीं।

एक तरफ राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाखों करोड़ों ऋण वापसी नहीं होने के कारण बट्टे खाते में पड़े हैं जो कि बड़े पूंजीपति जानबूझ कर पैसा वापिस नही कर रहे, लाखों करोड़ों रूपए इन दोषियों को हेयरकट के नाम पर बैंकरप्सी और इन्सोलवेंसीकोड के तहत दिए जा रहे है, ऋण मांफी या ऋण खारिज करने इत्यादि के माध्यम से पूंजीपतियों की सेवा की जा रही हैं, लेकिन सरकार और आई वी ए बैक कर्मचारियों और अधिकारियों की जायज मांगों पर समझौता नही कर रही।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkbl

jkT;	dn	uoEcj 2019	fnlEcj 2019
vk/k inn'k	xl.Vj	302	303
	fot ;ckMk	307	309
	fo'kk[kkiÝkue	310	316
vle	MeMek frulf[k;k	296	303
	xokgkVh	290	292
	ycd flYpj	286	285
	efj;kuh tkjgkV	275	281
	jxkikjk rt iij	269	268
fcgkj	e?kj&tekyiij	366	367
p.Mhx<	p.Mhx<	322	325
NÝkhlx<	fHkykbl	346	344
fnYyh	fnYyh	309	311
Xkkvk	xkvk	332	343
Xktjkr	vgenkckn	301	299
	Hkkouxj	307	309
	jktdkV	307	309
	ljr	292	289
	oMknjk	292	295
gfj;k.kk	Qjhnkckn	288	289
	;euk uxj	311	312
fgekpy	fgekpy çn'k	281	283
tEe ,o d'ehj	Jhuxj	290	292
>kj[k.M	ckdkjk	320	321
	fxfjMhg	361	370
	te'kniij	381	380
	>fj;k	378	380
	dkMek	408	406
	jkph gfV;k	412	418
dukVd	cyxke	315	324
	cxy#	305	308
	gcyh /kkjokM	348	353
	ejdjk	320	326
	elij	321	323
djy	,.kkdye@vyob	327	332
	el.MkD;ke	332	337
	fDoyku	368	372
e/; çn'k	Hkkikly	344	345
	fNnokMk	326	329
	bnkj	298	297
	tcyiij	337	337
महाराष्ट्र	मुम्बई	322	322
	ukxiij	407	405
	ukfld	377	380
	il.k	358	357
	'kkykiij	350	347
mMhlk	vkxy&rkypij	346	346
	jkmjdyk	337	342
ikfMpfj	ikfMpfj	326	334
itkc	verlj	356	357
	tkyU/kj	334	340
	yf/k;kuk	309	317
jktLFkku	vtej	297	300
	HkhyokMk	307	308
	t;ij	325	326
rfeyukMl	pUul	288	295
	dk;EcVj	300	307
	dUuj	345	349
	enjkbl	318	323
	lye	308	311
	fr#fpjkiYyh	310	322
ryxkuk	xknkojh[kkuh	346	348
	gnjkckn	275	278
	okjxy	328	332
f=ijk	f=ijk	277	280
mÝkj çn'k	vkxjk	375	377
	xkft;kckn	349	350
	dkuiij	357	361
	y[kuÅ	357	358
	okjk.klh	355	356
if'pe cxky	vklulky	356	356
	nkftfyx	287	290
	nxkiij	336	338
	gfYn;k	368	369
	gkoMk	302	305
	tkyikbxMh	296	295
	dkydkrk	299	303
	jkuhxt	309	316
	flyhxMh	302	302
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**328**	**330**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
~~आइएफसीकोड~~ : सीएनआरबी 0000158;

- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; फोनः (011) 23221306
फैक्सः (011) 23221284

राज्यों से

कर्नाटक

बंगलौर में एमडीएम वर्कर्स का विशाल धरना

(रिपोर्ट पृ. 25)

राजस्थान

निजीकरण के खिलाफ जयपुर में एलआईसी कर्मियों का विरोध

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स

¼Åij ck,i l½ (1) शहीद मशाल जत्था; (2) नेताजी को माल्यार्पण; (3) और (4) गणतंत्र दिवस पर प्रतिज्ञा और मानव श्रृंखला (5) कान्फ्रेन्स के समापन पर रैली का एक हिस्सा।